भारत की आउटवार्ड FDI प्रवृत्तियाँ

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

मार्च 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत के बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (OFDI) में **39%** की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई साथ ही यह 28.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया, जो अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थितियों के प्रभाव को दर्शाता है।

- गिरावट का मुख्य कारण **इक्विटी तथा लोन** दोनों माध्यमों में प्रतिबद्धताओं में कमी को दर्शाता है। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी अधिग्रहण में कमी ने भी इस गिरावट में भूमिका निभाई है।
- हालाँकि, मार्च 2024 में **बाह्य FDI** में वृद्धि देखी गई, जो 3.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, साथ ही इक्विटी प्रतिबद्धताएँ 2.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गईं, जो कि वित्तीय वर्ष के लिये सर्वाधिक है**।**
  - यह स्थिति चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच उभरते संभावित अवसरों को इंगित करती है, जो भारत के बाह्य FDI रुझानों की गतिशील प्रकृति का सूचक है।
- आउटवार्ड प्रत्यक्ष निवेश एक व्यावसायिक रणनीति है जहाँ एक देश में स्थित कंपनी दूसरे देश (मेज़बान देश) में स्थित एक व्यावसायिक इकाई (विदेशी सहयोगी) में निवेश करती है।
  - यह निवेश केवल स्टॉक या बॉण्ड खरीदने की तुलना में उच्च स्थिति रखता है क्योंकि इसमें विदेशी कंपनी में एक **नियंत्रित हित** या महत्त्वपूर्ण प्रभाव **स्थापित करना शामिल है**।

FDI और FPI

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

FDI:
- किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश

FDI के अंतर्वाह हेतु मार्ग :
- स्वचालित मार्ग:
  - किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है
  - गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक की अनुमति
- सरकारी मार्ग:
  - कुछ क्षेत्रों में या विशिष्ट सीमा से ऊपर के निवेश के लिये आवश्यक
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और RBI द्वारा प्रशासित

स्वचालित और सरकारी रूट के माध्यम से स्वीकृति के उदाहरण:
- बैंकिंग (निजी क्षेत्र): 49% तक (स्वायत्त) + 49% से ऊपर और 74% तक (सरकारी)
- रक्षा: 74% तक (स्वायत्त) + 74% से अधिक (सरकारी)
- हेल्थकेयर (ब्राउनफील्ड): 74% तक (स्वायत्त) + 74% से ऊपर (सरकारी)
- दूरसंचार सेवाएँ: 49% तक (स्वायत्त) + 49% से अधिक (सरकारी)

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB):
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है
- FDI प्रस्तावों को संसाधित करने के लिये ज़िम्मेदार - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) द्वारा सुविधा प्रदान की गई
- सरकार की मंज़ूरी के लिये सिफारिशें करना

भारत (चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्याँमार और अफगानिस्तान) के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

भारत के शीर्ष 5 FDI स्रोत (वित्त वर्ष 2022-23):
- मॉरीशस
- सिंगापुर
- अमेरिका
- नीदरलैंड
- जापान

FDI आकर्षित करने वाले भारत के शीर्ष क्षेत्र (वित्त वर्ष 2022-23):
- सेवा क्षेत्र
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
- व्यापार
- दूरसंचार
- ऑटोमोबाइल उद्योग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

FPI:
- वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों द्वारा किये गए निवेश
- फ्लाई बाय नाइट या हॉट मनी के नाम से जाना जाता है

महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:
- स्वामित्व प्राप्त किये बिना वित्तीय संपत्तियों की खरीद होती है
- निष्क्रिय निवेश दृष्टिकोण
- निवेशक लाभांश, ब्याज और पूंजी वृद्धि के माध्यम से रिटर्न अर्जित करते हैं

उदाहरण:
- स्टॉक, बॉण्ड आदि।

नियामक संस्था:
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

FDI और FPI के बीच अंतर

विशेषताएँ	FDI	FPI
निवेश की प्रकृति	दीर्घकालिक	अल्पकालिक
उद्देश्य	दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश	निवेश पर त्वरित रिटर्न अर्जित करना
नियंत्रण	महत्वपूर्ण (निवेशित इकाई पर)	नहीं या सीमित नियंत्रण
निवेश	मूर्त संपत्ति (जैसे, कारखाने, भवन)	वित्तीय संपत्ति (जैसे, स्टॉक, बॉण्ड)
रिटर्न्स	लाभ, लाभांश और पूंजी अभिमूल्यन	लाभांश, ब्याज, और पूंजी अभिमूल्यन
नीति विनियम	सरकार की नीतियाँ और क्षेत्र-विशिष्ट नियम	लचीले नियम और आसान प्रवेश/निकास
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	रोज़गार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास	अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है और शेयर बाज़ार को प्रभावित करता है

Drishti IAS

//

और पढ़ें: भारत के आउटवार्ड और इनवार्ड निवेश रुझान

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-outward-fdi-trends